



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237]
No. 237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1997/अग्रहायण 21, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 1997/AGRAHAYANA 21, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 60 (पी एन)/97-02

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

विषय :— अप्रैल, 1997 से मार्च, 2002 हेतु निर्यात और आयात-नीति—भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कम्पनियों द्वारा सी के डी/एस के डी किटों/संघटकों के आयात से संबंधित नीति ।

फा. सं. आई पी सी 4/5/(593)/92-97.—समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार उपर्युक्त विषय और भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कम्पनियों द्वारा सी के डी/एस के डी किटों/संघटकों के आयात हेतु वर्ष 1995 में निर्धारित मापदण्डों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन मापदण्डों पर अब पुनर्विचार किया गया है तथा संयुक्त उद्यम मोटर वाहन विनिर्माता कम्पनियों (मौजूदा और नई दोनों) को अब संशोधित मापदण्डों के अनुसार नए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

2. उपर्युक्त के अनुसार, सी के डी/एस के डी रूप में मोटर वाहनों हेतु संघटकों का आयात, जो कि मौजूदा निर्यात आयात नीति के तहत प्रतिबंधित है, लाइसेंस के तहत अनुमत होगा और ऐसा लाइसेंस इन कम्पनियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के आधार पर केवल संयुक्त उद्यम की आटोमोबाइल विनिर्माता कम्पनियों को जारी किया जाएगा । इस प्रकार सभी संयुक्त उद्यम विनिर्माता सी के डी/एस के डी किटों/संघटकों के आयात हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे ।

3 समझौता-ज्ञापन निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित होगा :—

- (1) कारों के विनिर्माण न कि आयातित किटों/संघटकों के संयोजन के लिए वास्तविक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना ।
- (2) यदि संयुक्त उद्यम में विदेशी स्वामित्व अंश की अधिकता है तो प्रचालन प्रारम्भ होने से प्रथम तीन वर्षों के भीतर विदेशी भागीदार द्वारा देश में कम से कम 50 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा लाई जाएगी । तथापि, यह शर्त केवल नए संयुक्त उद्यम कम्पनियों पर लागू होगी ।
- (3) सी के डी/ एस के डी किटों/संघटकों की प्रथम आयात खेप की निकासी की तारीख से तीसरे वर्ष में या पहले 50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक और 5वें वर्ष में या पहले 70 प्रतिशत तक संघटकों का स्वदेशीकरण । एक बार जब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली फर्म 70 प्रतिशत के स्वदेशीकरण स्तर को प्राप्त कर लेती है तो उसे विदेश व्यापार महानिदेशालय से आगे कोई और आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

परिणामस्वरूप जब फर्म 70 प्रतिशत स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लेती हैं तो वे स्वतः समझौता ज्ञापन की सीमा से बाहर हो जाएगी। तथापि, उन्हें उस समय तक उनके द्वारा किए गए आयातों के अनुरूप निर्यात दायित्व का निष्पादन करना होगा।

- (4) निर्यात दायित्व के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली फर्मों को, सी के डी/एस के डी क्वोटों/संचटकों के आयात के वास्तविक लागत-बीमा भाड़ा मूल्य और उक्त अवधि के दौरान कारों और आटो संचटकों के निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बीच सन्तुलन बनाए रखने के लिए समझौता ज्ञापन की सारी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा के व्यापक निष्प्रभाव को प्राप्त करना होगा। निर्यात दायित्व की अवधि उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष से प्रारम्भ होगा। उत्पादन आरम्भ होने की तारीख उत्पादन शुल्क के भुगतान के बाद फैक्टरी से प्रेषण की प्रथम निकासी की तारीख मानी जाएगी, लेकिन उत्पादन शुरू होने की इस तारीख विशेष से दो वर्षों का विलम्बन काल होगा जिसके दौरान फर्म को किसी भी निर्यात वायदे को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, तीसरे वर्ष से आगे (पहली खेप की निकासी की तारीख से प्रभावी) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली फर्म को समझौता ज्ञापन की शेष अवधि के लिए निर्यात दायित्व की पूर्ति करनी होगी, जब तक फर्म समस्त निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर लेती। चौथे वर्ष से सी के डी/एस के डी आयातों का मूल्य, समझौता ज्ञापनों के अनुसार विगत वर्ष में पूरे किए गए निर्यात दायित्व के सन्दर्भ में विनियमित किया जाएगा। निर्यात वायदे को कारों के साथ-साथ आटो संचटकों के निर्यात से पूरा किया जाएगा। यह निर्यात दायित्व ई पी सी जी सम्बन्धी निर्यात दायित्व के अलावा होगा।

4. यह समझौता ज्ञापन स्कीम आयात लाइसेंसिंग तंत्र के माध्यम से लागू की जाएगी और डी जी एफ टी द्वारा उपर्युक्त पैरामीटरों के आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली फर्मों को आयात लाइसेंस दिए जाएंगे।

5. उपर्युक्त तत्वों के सम्बन्ध में प्रगति की निगरानी के लिए सभी संयुक्त उद्यम ऊपर दिए गए मानदण्डों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इन मानदण्डों के सम्बन्ध में की गई प्रगति का एक संयुक्त वार्षिक पुनरीक्षण वाणिज्य मंत्रालय डी आई पी पी और राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. ये संशोधित दिशा-निर्देश इस क्षेत्र के सभी मौजूदा और भावी सदस्यों पर लागू होंगे।

7. उपर्युक्त बातों के अपवाद स्वरूप हल्के या भारी वाणिज्यिक वाहनों, ट्रैक्टर, अर्थमूविंग उपकरणों आदि हेतु विदेशी सहयोग के तहत विनिर्माण यूनिटों की स्थापना की इच्छुक कम्पनियों को किसी भी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सी के डी/एस के डी आयातों के लिए उनके अनुरोध पर विशेष लाइसेंसिंग समिति द्वारा गुणदोष वार्षिक आधार पर विचार किया जाएगा।

8. इस सार्वजनिक सूचना के साथ अनुलग्नक के रूप में समझौता-ज्ञापन के लिए मानक प्रपत्र संलग्न है और समझौता ज्ञापन को इस प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाना है।

9. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल संख्या आई पी सी 4/5 (593)/92-97 में जारी]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना संख्या 60 (पी एन)/97-02 दिनांक 12-12-97 का अनुलग्नक

समझौता ज्ञापन

1. यह समझौता ज्ञापन दिनांक माह 1997-98 को विदेश व्यापार महानिदेशक (जिसका इसके बाद डी जी एफ टी के रूप में उल्लेख किया जाएगा) उद्योग भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार

और

मेम्बर (जिसका इसके बाद पार्टी के रूप में उल्लेख किया जाएगा) इस अभिव्यक्ति में उनके निष्पादक, उत्तराधिकारी,

परासक और प्रतिनिधि शामिल होंगे।

के बीच

निष्पादित किया गया है।

2. जबकि पार्टी ने कारकों के निर्माण हेतु सी के डी/एस के डी संघटकों के आयात को कवर करने के लिए आयात लाइसेंस जारी करवाने का अनुरोध किया है ।

3. और जबकि पार्टी संयुक्त उद्यम के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करेगी :

- (1) कि पार्टी विदेशी सांझेदार मैसर्स.....के.....अमरीकी डालर (.....रुपये) के इक्विटी शेयरों के साथ इस संयुक्त उद्यम में.....रुपये का निवेश करेगी जो नीचे उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में होगा :

वर्ष	मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में विदेश सहयोगी के इक्विटी अंशदान (रुपये करोड़ों में)	कुल निवेश (रुपये करोड़ों में)
	अमरीकी डालर मिलियन में ।	अमरीकी डालर मिलियन

- (2) कि यदि संयुक्त उद्यम के स्वामित्व में अधिकांश विदेशी इक्विटी है तो प्रचालन के शुरू होने के प्रथम तीन वर्ष के अन्दर विदेशी भागीदार को 50 मिलियन यू.एस. डालर की न्यूनतम विदेशी इक्विटी प्रस्तुत करनी होगी ।
- (3) कि पार्टी को भारत में कारों का उत्पादन करने के लिए मात्र असम्बन्धी सुविधाएं नहीं बल्कि वास्तविक मैनुफैक्चरिंग सुविधाएं देनी होंगी । वर्षवार उत्पादन मात्रा निम्नलिखित होगी ।

वर्ष	उत्पादन मात्रा (संख्या)
------	-------------------------

- (4) कि पार्टी को सी के डी/एस के डी किट्स के प्रथम आयात प्रेषण की निकासी की तिथि से तीन वर्ष या उससे पहले 50 प्रतिशत और पाँच वर्ष या उससे पहले 70 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक संघटकों का स्वदेशीकरण प्राप्त करना होगा । एक बार यदि पार्टी ने 70 प्रतिशत के स्वदेशीकरण स्तर को प्राप्त कर लिया है तो उसे विदेशी व्यापार महानिदेशालय से अगले आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि पार्टी को उस समय तक उनके द्वारा किए गए आयात के तदनु रूप निर्यात दायित्व का निर्वहन करना होगा ।

पार्टी अपने उत्पाद के, वर्षवार, स्वदेशीकरण के निम्नलिखित स्तरों को प्राप्त करना चाहती है :—

वर्ष	स्वदेशीकरण की प्रतिशतता (%)
	पार्टी स्थानीय आपूर्ति आधार और संबंधित स्थानीय अंश के विकास को यथासंभव शीघ्र तत्परता से लागू करेगी और प्राप्त करेगी चूंकि इससे स्वदेशीकरण का उच्च स्तर प्राप्त हो सकेगा ।

- (5) कि पार्टी पांच वर्षों में उल्लिखित अनुसार लागत बीमा भाड़ा मूल्य के साथ किटों की निम्नलिखित संख्या का आयात करना चाहती है :—

वर्ष	किटों की संख्या	लागत बीमा भाड़ा मूल्य (करोड़ रुपयों में मिलियन अमेरिकन डालर)
------	-----------------	---

- (6) कि उक्त अवधि में सी के डी/एस के डी/संघटकों के आयातों के वास्तविक लागत बीमा भाड़ा मूल्य और कारों व आटो संघटकों के निर्यात के पोत पर्यप्त निःशुल्क मूल्य के बीच संतुलन बनाने की दृष्टि से पार्टी समझौता जापन की समस्त अवधि में विदेशी मुद्रा के व्यापक निष्प्रभावन को प्राप्त करेगी ।

निर्यात दायित्व अवधि उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष से प्रारम्भ होगी । उत्पादन शुरू होने की तारीख ही उत्पाद शुल्क के भुगतान के बाद फैक्टरी में प्रेषण की पहली रिहाई की तारीख मानी जाएगी किन्तु उत्पादन के शुरू होने की इस विशेष तारीख से दो वर्षों का विलम्बन काल होगा जिसके दौरान फर्म को कोई निर्यात दायित्व पूरा करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, तीसरे वर्ष के बाद (प्रथम प्रेषण की रिहाई की तारीख से प्रभावी) समझौता जापन अवधि की शेष अवधि के लिए उस समय तक समझौता जापन करने वाली फर्म को उनके द्वारा किए गए आयातों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बराबर

निर्यात दायित्व पूरा करना होगा जब तक कि वे सारा निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर लेते। चौथे वर्ष के बाद सी के डी/एस के डी के आयातों का मूल्य समझौता जापान के अनुसार पूर्व वर्ष में पूरे किए गए निर्यात दायित्व के सन्दर्भ में निर्गमित किया जा सकता है। निर्यात दायित्व केवल कारों और ऑटो संघटकों के निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा यह निर्यात दायित्व इ.पी.सी.जी. सम्बद्ध निर्यात दायित्व के अतिरिक्त होगा।

पार्टी निम्नलिखित अनुसार, वर्षवार, कारों और ऑटो संघटकों के निर्यात को प्राप्त करना चाहती है।

वर्ष निर्यात (रु. करोड़) निर्यात (दस लाख अमरीकी डालरों में)

4. उपर्युक्त निर्धारित तत्वों के सम्बन्ध में प्रगति की जाँच के लिए पार्टी उपर्युक्त रेखांकित पैरामीटरों पर महानिदेशक, विदेश व्यापार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इन्हीं पैरामीटरों के सम्बन्ध में की गई प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर पार्टी को आगे लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

5. समझौता-जापान योजना आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया के जरिए लागू की जाएगी और समझौता जापान हस्ताक्षर करने वाली फर्मों को उपर्युक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट पैरामीटरों के सम्बन्ध में की गई प्रगति के आधार पर महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा आयात लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

(प्रबन्ध निदेशक)

(महानिदेशक, विदेश व्यापार)

वे ----- की ओर से

भारत सरकार की ओर से

साक्षी

साक्षी

1.

1.

2.

2.

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 60 (PN)/97-02

New Delhi, the 12th December, 1997

Subject : Export and Import Policy April, 1997—March, 2002—Policy relating to import of CKD/SKD kits/components by Joint Venture Car manufacturer companies under MOU to be signed with the Government of India.

F.No. IPC/4/5(593)/92-97.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002 as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby draws attention to the above subject and the parameters stipulated in the year 1995 for import of CKD/SKD kits/components by the Joint Venture Motor Vehicle manufacturer companies under Memorandum of Understanding to be signed by them with the Government of India. These parameters have now been reviewed in the light of the changed circumstances and joint venture motor vehicle manufacturing companies (both existing and new) are required now to sign a fresh MOU with the Government of India as per the revised parameters.

2. Pursuant to the above, import of components for motor vehicle in CKD/SKD form, which is restricted for import under the current Export-Import Policy, shall be allowed for importation against a licence and such a licence will be issued only to Joint Venture automobile manufacturing companies on the basis of an MOU to be signed by these companies. Thus, all joint venture manufacturers shall enter into an MOU with DGFT for import of CKD/SKD kits/components.

3. The MOU shall be based on the following parameters :—

- (i) Establishment of actual production facilities for manufacture of cars and not for mere assembly of imported kits/components.
- (ii) A minimum foreign equity of US \$ 50 Million to be brought in by the foreign partner within the first three years of start of operations, if the Joint Venture involves majority foreign equity ownership. However, this condition will apply to new Joint Venture companies only.
- (iii) Indigenisation of components upto a minimum level of 50% in the third year or earlier from the date of clearance of first import consignment of CKD/SKD Kits/components and 70% in the 5th year or earlier. Once the MOU signing firm has reached an indigenisation level of 70%, there will be no need for further import licences from

DGFT. Consequently, as and when the firms achieve 70% indigenisation, they would go outside the ambit of the MOU automatically. However, they will discharge the export obligation corresponding to the imports made by them till that time.

- (iv) Regarding export obligation, the firms entering into MOU would achieve abroad neutralization of foreign exchange over the entire period of the MOU in terms of balancing between the actual CIF value of imports of CKD/SKD Kits/components and the FOB value of exports of cars and auto components over the said period. The period of export obligation would commence from the third year of commencement of production. The date of commencement of production would be deemed to be the date of the first release of consignment from factory after payment of excise duty, but there would be a moratorium of two years from this particular date of commencement of production during which the firm need not fulfil any export commitment. However, from the third year onwards (effective from date of release of first consignment), the MOU signing firm would have an export obligation equivalent to the cif value of imports made by them till that time for the remainder of the MOU period till they complete the entire export obligation. From 4th year onwards the value of imports of CKD/SKD may be regulated with reference to the export obligation fulfilled in the previous years as per the MOU. The export commitment would be met by export of cars as well as auto components. This export obligation will be over and above the EPCG related export obligation.

4. The MOU Scheme would be enforced through the import licensing mechanism and MOU signing firms would be granted import licences by DGFT based on above parameters.

5. To monitor the progress in respect of the elements stipulated above all the Joint Ventures would submit annual reports to the DGFT on the parameters outlined above and a Joint Annual Review of the progress made in respect of these parameters would be undertaken by Ministry of Commerce, DIPP and Department of Revenue.

6. These revised guidelines will apply to all existing and future entrants into this sector.

7. By way of exception to the foregoing, companies intending to set up manufacturing units under foreign collaboration for light or heavy commercial vehicles, tractors, earthmoving equipments etc will not be required to enter into any MOU. Their requests for ckd/skd imports shall be considered by the Special Licensing Committee on merits on an annual basis.

8. A standard format for MOU is enclosed as an appendix to this Public Notice and MOU is required to be signed as per this format.

9. This issues in public interest.

[Issued from File No. IPC/4/5 (593)/92-97]

sd :

(N.L. LAKHANPAL)

DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE

(RAJAN SUDESH RATNA)

Dy. DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE

Copy to all concerned;

By Order etc.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

I. This MOU has been made on—day of, 1997/1998.

BETWEEN

Government of India acting through the Director General of Foreign Trade (hereinafter referred to as the D.G.F.T) Udyog Bhawan, New Delhi.

AND

M/s. _____

(hereinafter referred to as the party which expression shall be deemed to include their executors, successors, administrator and assignee).

II. Whereas the party has sought issue of an import licence to cover import of CKD/SKD parts for manufacture of cars.

3165-41/97-2

III. And whereas the party shall do the following by way of implementation of the Joint Venture :

(i) that the party shall make an investment of Rs. in this joint venture with equity share of US/\$ (Rs.) of M/s. the foreign partner, which will be in freely convertible currency as per the time frame mentioned hereunder :

Year	Foreign collaborator's Equity contribution in freely convertible currency. (Rs. in crores) (US\$ in Million)	Total investment (Rs. in crores) (US \$ in Millions)
------	--	--

(ii) that a minimum foreign equity of US\$ 50 million to be brought in by the foreign partner within the first three years of start of operations, if the joint venture involves majority foreign equity ownership.

(iii) that the party shall establish actual manufacturing facilities, and not mere assembly facilities, in India to produce cars. The following will be production volumes year-wise :—

Year	Production Volumes (Numbers)
------	------------------------------

(iv) that the party shall achieve indigenisation of components upto a minimum level of 50% in the third years or earlier from the date of clearance of first import consignment of CKD/SKD kits and 70% in the fifth year or earlier. Once the party has reached an indigenisation level of 70% there will be no need for further import licence from DGFT. However, the party shall discharge the export obligation corresponding to the imports made by them till that time.

That the party intends to achieve the following levels of indigenisation of their product, year-wise :—

Year	Percentage (%) of indigenisation
------	----------------------------------

The party shall aggressively pursue and achieve as soon as possible the development of the local supply base and increased local content, since the same will allow a higher level of indigenisation.

(v) that the party intends to import the following number of kits with CIF value as indicated in the first five years :

Year	No. of kits	CIF Value (Rs. in crores (US\$ in Million))
------	-------------	--

(vi) that the party shall achieve a broad neutralisation of foreign exchange over the entire period of the MOU in terms of balancing between the actual CIF value of imports of CKD/SKD components and the FOB value of export of cars and auto components over the said period. The period of export obligation would commence from the third year of commencement of production. The date of commencement of production, would be deemed to be the date of the first release of consignment from factory after payment of excise duty, but there would be a moratorium of two years from this particular date of commencement of production during which the firm need not fulfil any export commitment. However, from the third year onwards (effective from date of release of first consignment), the MOU signing firm would have an export obligation equivalent to the cif value of imports made by them till that time for the remainder of the MOU period till they complete the entire export obligation. From 4th year onwards the value of imports of CKD/SKD may be regulated with reference to the export obligation fulfilled in the previous year as per the MOU. The export commitment would be met by export of only cars as well as auto components. This export obligation will be over and above the EPCG related export obligation.

That the party intends to achieve export of cars and auto components as under year-wise :—

Year	Export (Rs. crores) exports (US\$ in Million)
------	---

IV. To monitor the progress in respect of the elements stipulated above the party shall submit annual reports to the DGFT on the parameters outlined above and further licences will be issued to the party on the basis of an annual report of the progress made in relation to these parameters.

V. The MOU scheme would be enforced through the import licensing mechanism and MOU signing firms would be granted

import licences by DGFT based on the progress made in respect of the parameters mentioned at para III above.

()

Managing Director

On behalf of

M/s.-----

()

Director General of Foreign Trade

On behalf of Govt. of India

Witnesses

1

2.

Witnesses

1.

2.

